मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

शतुरमुर्ग बनी खट्टर सरकार 3
विपक्ष के पास है बड़ा जनाधार 4
क्या मैं भी चुनाव हार गया हूं 5
वेलकम राष्ट्रवादी महंगाई 6
हरियाणा चुनावी विश्लेषण 8

वर्ष 32 अंक -29 फ़रीदाबाद 2-8 जून 2019 फोन -8851091460 2.5₹

फरीदाबाद पुलिस द्वारा थाने में लाकर महिला की अपमानजनक पिटाई का प्रकरण

वीडियो वायरल होने पर नपे पांच पुलिसकर्मी : डीजीपी खामोश

वीडियो वायरल न होता तो सब ठीक था : क्या पुलिस को गैरकानूनी ढंग से काम करने का लाइसेंस मिला हुआ है ? न मुख्यमंत्री खट्टर, जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, और न डीजीपी मनोज यादव, जो पुलिस सुधार की बात करते हैं, ने एसपीओ व्यवस्था की खामियों का जायजा लेने की जहमत उठाई है। जबकि थानों के लिये उगाही से लेकर ट्रैफ़िक लूट और गैरकानूनी बल प्रयोग में ये एसपीओ पुलिस विभाग के अग्रणी एजेंट बने हुए हैं।

बल्लबगढ़ (म.मो.) अक्टूबर 2018 को देर शाम एक महिला किसी पुरुष के साथ पार्क में बैठी थी। सूचना पाकर आदर्श नगर थाने की 'मुस्तैद' टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुरुष तो इस 'बहादुर' टीम के हाथ आया नहीं लेकिन आसान शिकार के तौर पर महिला को दबोच लिया। थाने के लॉन में लाकर दो हवलदारों व तीन एसपीयों (एस्पेशल पुलिस अफ़सरों) ने महिला से पूछताछ शुरू की। पांचों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। पूरी बदतमीजी के साथ उससे बेहूदा सवाल पूछे जाने लगे। इस बीच एक हवलदार चमड़े के पटे को दोनों हाथों से घुमा कर उसके पिछवाड़े पर मार रहा था।

कानूनन दिन छिपे के बाद किसी भी महिला को थाने में नहीं लाया जा सकता। यदि बहुत ही जरूरी हो तो महिला पुलिसकर्मी की हाजरी में ही उसे लाया जा सकता है परन्तु उक्त मामले में तो पांचो पुरुष पुलिसकर्मी उसको लपेटे खड़े वीडियो में नज़र आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद धूल-धुसरित हो चुकी पुलिस की छवि को झाड़-पोछ कर साफ़-सुथरी करने के लिये पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने 'तुरंत' एक्शन लेते हुए दोनों हवलदारों- बलदेव तथा रोहित को सस्पेंड और तीनों एसपीयों को बर्खास्त कर दिया। इसके साथ-साथ पांचों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323, 509 व 342 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश भी कर दिया जहां से उनकी जमानतें हो गई।

अदालती मुकदमे को सिरे चढ़ाने की एक लम्बी व थका देने वाली प्रक्रिया चलती है। इसके लिये मजबूत शिकायतकर्ता व गवाहों का होना बहुत जरूरी है। इसके लिये पीड़ित महिला की तलाश की जा रही है। समझने वाली बात यह है कि जो पीड़ित महिला इतनी दबी कुचली है कि अपनी इस दुर्गति की शिकायत तक खुद न कर सकी हो वह कहां तक इन पुलिस वालों के सामने कोर्ट में खड़ी रह पायेगी ? जाहिर है कि उसे घुमा-फिरा कर ऐसे रास्ते पर ले आया जायेगा जहां से दोषी पुलिसकर्मी साफ बच निकलेंगे।

अदालती कार्यवाही के अलावा दोनों हवलदारों के खिलाफ़ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिये गये हैं। इस जांच के आधार पर उच्च पुलिस अधिकारियों को इन दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करने तक के अधिकार होते हैं। इसके लिये उन अधिकारियों को कोई बहुत ज्यादा कागजी कार्यवाही की आवशयकता नहीं होती। इसके लिये जरूरत होती है केवल साफ़ नीयत व इंसाफ़ करने की भावना की।

यहां एक गम्भीर प्रश्न यह पैदा होता है कि थाने में क्या उन दो हवलदारों के अलावा कोई बड़ा अफ़सर मौजूद नहीं था? क्या एसएचओ अथवा अतिरिक्त एसएचओ व अन्य अधिकारियों की कोई जिम्मेवारी नहीं थी? क्या ये सब लोग चुपचाप तमाशा देखने के बाद गुनाह में शामिल नहीं समझे जायेंगे? मात्र एक किलोमीटर के फ़ासले पर बैठे एसीपी व डीसीपी को जब यही न पता चल सके कि उनके अधीन थानों में क्या हो रहा है तो उनके बने रहने का क्या औचित्य है? यदि यह वीडियो वायरल न हुआ होता तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था और पुलिस की छवि बल्ले-बल्ले कर रही थी।

संदर्भवश पाठक जानना चाहेंगे कि यह एसपीओ क्या होता है? यह फ़र्जी पुलिस की एक अलंकृत संज्ञा है। आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मी भर्ती करके उन्हें बेहतरीन ट्रेनिंग देकर जनता की सेवा में लगाने की अपेक्षा खट्टर सरकार ने एक शॉट-कट रास्ता फ़र्जी पुलिस खड़ी करने का अखत्यार कर रखा है। इसके अनुसार फ़ौज से रिटायर हुए जवानों को पुलिस की बर्दी पहना कर चौदह हज़ार प्रति माह वेतन पर भर्ती कर लिया जाता है। इनकी न तो कोई जिम्मेवारी होती है और न ही कोई समझदारी। वैसे भी ये लोग एक-एक साल के ठेके पर रखे जाते हैं।

जनता को बहकाने में कामयाब गूजर दोबारा मंत्री बने

फ़रीदाबाद (म.मो.) पूरे पांच साल तक यमुना पर मंझावली पुल, स्मार्ट सिटी, गुड़गांव तक मैट्रो रेल का झांसा देने तथा आधे-अधूरे बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनेकों नारियल फ़ोड़ने, नगर निगम द्वारा बनायी जाने वाली सड़कों व सीवर लाइन के शगूफ़े छोड़ने तथा चिकित्सा के नाम पर मोदी के 'आयुष्मान भारत' का नगाड़ा बजाने भर से कृष्णपाल गूजर पिछली बार से भी अधिक मतों से जीत गये। यह और बात है कि उनके मुकाबले में कांग्रेस ने बेहद पिटा चुनावी मोहरा अवतार भड़ाना को उतार कर गूजर की राह आसान कर दी थी।

दिल्ली-पलवल के बीच बिछने वाली चौथी रेलवे लाइन इन पांच सालों में एक इंच भी आगे न बढ सकी। ओल्ड फ़रीदाबाद स्टेशन की अधूरी बिल्डिंग वहीं तक है जहां 2014 से पहले थी। स्टेशन पर प्लेटफ़ार्म पार करने हेतु जो स्वचालित सीढी लगाई थी वह गूजर द्वारा नारियल फ़ोड़ने के सप्ताह भर बाद ही ठप हो गयी थी। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ईएसआईसी के तमाम अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में न तो पर्याप्त डॉक्टर व अन्य स्टाफ़ हैं और न ही आवश्यक उपकरण व दवायें आदि। और तो और अगस्त 2018 से रैबीज़ (कुत्ता काटे) के टीके तक नहीं हैं। तमाम सरकारी स्कूलों में शिक्षकों व अन्य सुविधाओं के अभाव में परीक्षा परिणाम ज़ीरो प्रतिशत आ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ दिये जाने पर स्कूल ही बंद कर दिये जा रहे हैं।

दूसरी ओर गूजर व उनके मामा तथा अन्य लगुए-भगुए जम कर, पांच साल तक लूट-मार करते रहे। पुलिस व अन्य महकमों का खुला दुरुपयोग, ज़मीनों-जायदादों पर कब्ज़े, अरावली व यमुना में अवैध खनन करा कर अकूत धन संचय किया जिसका पूरा विवरण समय-समय पर मीडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा। बीते पूरे पांच साल में गूजर ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसे उनकी उपलब्धि के तौर पर गिना जा सके। और तो ओर दिल्ली-पलवल के बीच चलने वाली ट्रेनों की संख्या अथवा उन्हीं ट्रेनों में डिब्बों की संख्या तक नहीं बढवा सके जिसकी वजह से यात्रियों को भूसे की तरह ठुंस-ठुंस कर यात्रा करनी पड़ती है। इतना ही नहीं साल में 2-4 सप्ताह के लिये किसी न किसी बहाने यह रेल सेवा भी बंद कर दी जाती है;कभी धुंध के नाम पर तो कभी बरसात के नाम पर तो कभी सिग्नल व इन्टरलॉकिंग के नाम पर। वर्ष 2014-15 के बजट में जब रेलवे ने मंथली पास के रेट बढाये थे तो मुंबई के सांसदों ने अपनी ताकत से उस बढोत्तरी को वहां लागू नहीं होने दिया, लेकिन गूजर की हिम्मत नहीं हुई, इस बाबत मुंह तक खोलने की।

ऐसा नहीं है कि अकेले गूजर ही पांच साल तक निकम्मे रहे, बल्कि खट्टर सरकार व मोदी सरकार ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका जरा सा भी लाभ समाज के बड़े एवं वंचित तबकों को हुआ हो। पूरे चुनाव में उस एजेंडे का तो जिक्र तक नहीं किया गया जिसे लेकर 2014 में मोदी सरकार आई थी। अपनी तमाम नाकामियों एवं घोटालों को ढकने के लिये बस एक राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व की चादर ही काफ़ी रही। ताज्जुब की बात तो यह है कि राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति उन लोगों से सीखनी पड़ रही है जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ हुकूमत के तलबे चाटते रहे और आज़ादी के लिये लड़ने वालों के विरुद्ध मुखबरियां करते रहे।

कुल मिला कर गूजर ने मोदी के नाम पर वोट लिये; दोनों ने साझे तौर पर यह साबित कर दिया है कि विकास के नाम पर, शिक्षा व चिकित्सा के नाम पर, रोज़गार व ग़रीबी के नाम पर, अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं। इन चुनावों में यह सिद्ध हो गया है कि जनता को उक्त कोई सुविधा देने की कतई कोई जरूरत नहीं। इन से वोट लेने के लिये 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम', हिन्दुत्व तथा पाकिस्तान का हव्वा ही काफ़ी है। अब देखना यह है कि भाजपा एवं संघ की यह रणनीति कब तक कारगर रहती है।

अगर कोई हिंदू बलात्कारी को बचाए जाने पर खुश होता है तो कौम अपनी मौत खुद लिख रही है

कठुआ में मुस्लिम बच्ची आसिफा के साथ मंदिर में बलात्कार किया गया था। उसके साथ बलात्कार के आरोप में मंदिर का पुजारी और उसके रिश्तेदार जेल में थे।

जम्मू कश्मीर में सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी भाजपा के विधायक और नेताओं ने बलात्कारी पुजारी के समर्थन में रैलियां करीं जिसमें तिरंगे झंडे लहराए गए। अदालत की कार्यवाही रोकने की कोशिश करी गई और चार्जशीट फाइल ना हो सके उसके लिए अदालत की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई गई।

और अंत में भाजपा ने चलती हुई जम्मू कश्मीर सरकार से समर्थन वापस ले लिया जिससे जम्मू कश्मीर की सरकार गिर गई। इसके बाद आतंकवाद का नया दौर शुरू हुआ और भारत के अनेकों सैनिक मारे गए।

भाजपा ने एक बलात्कारी पुजारी को बचाने के लिए सैकड़ों जवानों की जिंदगी खत्म कर दी। अब अदालत ने पुजारी और उसके रिश्तेदारों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है।

भाजपा ने पूरी की पूरी सरकार गिराने का जो फैसला किया था वह बलात्कारियों को बचाने के लिए किया था। भाजपा एक तरफ बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ बलात्कारियों को बचाने के लिए सरकारी तक गिरा देती है। इस पूरे प्रकरण में भाजपा ने जनता को यह संदेश देने की कोशिश करी है कि हमारे लिए किसी महिला की अस्मत से ज्यादा हिंदू भावनाओं को खुश करने की राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई हिंदू किसी बलात्कारी को बचाए जाने पर इसलिए खुश होता है क्योंकि वह उनके धर्म का एक पुजारी था तो यह कौम अपनी मौत खुद लिख रही है। जो कौम बलात्कारियों को अपनी धर्म का होने के कारण बचाए और इज्जत दे वह धर्म है ही नहीं वह पूरी तरह अधर्म है और यह झूठा धर्म बहुत जल्दी मिट जाएगा।

पाप और झूठ के दम पर कोई भी कौम जिंदा नहीं रह सकती।

-हिमांशु कुमार